प्रेस सूचना ब्यूरो
भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग

30 दिसंबर 2015

असैन्य नाभिकीय सहयोग - ठोस उपलब्धियों भरा वर्ष

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2015 में असैन्य नाभिकीय सहयोग के क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियाँ प्राप्त की गयी हैं।

प्रधानमंत्री द्वारा जनवरी 25-27, 2015 को, नयी दिल्ली में राष्ट्रपति ओबामा की मेजबानी के दौरान यू.एस. के साथ असैन्य नाभिकीय सहयोग करार के कार्यान्वयन को पुन: पटरी पर लाया गया। उसके बाद से, करार की कार्यान्वित करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए हैं और असैन्य नाभिकीय दायित्व पर हुई सहमति को कार्यान्वित करने हेतु इंडिया न्यूक्लीयर इंश्योरेंस पूल की स्थापना की गयी। जिससे भारत के "नाभिकीय क्षति हेतु असैन्य दायित्व अधिनियम 2010" के बारे में अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू चिंताओं का समाधान हो गया है। मीठी विर्दी, गुजरात में ए. पी. 1000 रिएक्टर की 6 यूनिटों के निर्माण हेतु एनपीसीआइएल एवं वेस्टिंगहाउस के बीच वाणिज्यिक वार्ताएं 2016 में पूरी होने के मार्ग पर है।

इस वर्ष के दौरान रूस और फ्रांस के साथ भी असैन्य नाभिकीय सहयोग आगे बढ़ा है। प्रधानमंत्री की अप्रैल 2015 की फ्रांस यात्रा के दौरान महाराष्ट्र की जैतापुर परियोजना के स्थानीयकरण की वृद्धि द्वारा लागत में कमी के उद्देश्य से मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो तथा मेसर्स अरेवा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 22 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री की रूस यात्रा रूस के दौरान डिजाइनीकृत नाभिकीय बिजली संयंत्रों हेतु भारत में विनिर्माण के स्थानीयकरण हेतु कार्रवाई के संयुक्त कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए। रूसी सहयोग से कम से कम 12 रिएक्टर यूनिटें स्थापित की जाएंगी।

अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री की कनाड़ा यात्रा के दौरान यूरेनियम की दीर्घावधि आपूर्ति हेतु कांट्रैक्ट (संविदा) पर हस्ताक्षर के बाद यूरेनियम का पहला कंसाइनमेंट (खेप) दिसंबर 2015 में भारत पहुंचा। इसी तरह जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री की कजाकस्तान यात्रा के दौरान यूरेनियम की खरीद हेतु एक दीर्घावधि कांट्रेक्ट (संविदा) पर हस्ताक्षर किए गए।

एक बड़ी प्रगति यह हुई है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ एक असैन्य नाभिकीय सहयोग करार और इसके साथ ही करार को कार्यान्वित करने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था 13 नवंबर 2015 को लागू हुई। कनाडा, कजाकस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ की गयी ईंधन सप्लाइ व्यवस्थाओं से भारत में नाभिकीय बिजली के विस्तार को समर्थन मिलने से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी।

जापान के प्रधानमंत्री श्री आबे की 12 दिसंबर 2015 की भारत यात्रा के दौरान एक द्विपक्षीय असैन्य नाभिकीय सहयोग करार पर सहमति होने से इस मुद्दे पर 05 वर्षों से चली आ रही बातचीत पूरी हो गयी। यह नवोन्मेषी घटना दोनों नेताओं के स्तर पर मजबूत इरादों से पूरी हो पायी।

स्वदेश में की गयी पहलों, विशेषत: एनपीसीआइएल को अन्य पीएसयू के साथ संयुक्त उद्यमों को स्थापित करने में समर्थ बनाने हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन के संसद में पारित होने के साथ, उपरोक्त करारों ने भारत में नाभिकीय ऊर्जा के विस्तार हेतु एक ठोस आधार बना दिया है। अंतत: एक संभावना युक्त क्षेत्र कार्यान्वित होने हेतु ऊर्जस्वित हो गया है।

****